राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

(शिक्षा)

1984-85

शिक्षा विभाग

राजस्थान

NIEPA DC
D02716

— 544
370.6
FAJ - U

राजस्थान में शिक्षा की प्रगति
1984-85

वर्ष 1984–85 के शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक व संख्यात्मक विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए गये जिनके फलस्वरूप शाला जाने वाले छात्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास सुधार व विस्तार हुआ। आलोच्य वर्ष में शिक्षा एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर किए गये व्यय के सम्बन्ध में तथा शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में संक्षिप्त प्रगति विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है—

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान देश के उन नौ राज्यों में से है जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अथक सुनियोजित प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा में और साक्षरता में काफी वृद्धि हुई है फिर भी 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत अभी भी 24·38 है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 11·42 ही है जबकि भारत का साक्षरता प्रतिशत 36·17 है और महिला साक्षरता प्रतिशत 24·30 है। इस दिशा में राज्यसरकार निरन्तर प्रयासरत है और इन प्रयासों में वृद्धि का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा

वर्ष 1984–85 में जनता की माँग, क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं राज्य के शैक्षिक विकास को दृष्टि में रखते हुए राज्य में 4,353 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं जिनमें से 4,253 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में तथा 100 विद्यालय शहरी क्षेत्र में खोले गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 4,016 छात्रों के तथा 237 छात्राओं के विद्यालय खोले गये हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में छात्रों के 90 तथा 10 छात्राओं के विद्यालय खोले गये हैं।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B.Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No. 2716
Date. 27-10-85

प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों की पूर्ति हेतु इस वर्ष 3,000 अतिरिक्त अध्यापकों के पद राज्य योजनान्तर्गत सृजित किए गये हैं। भारत सरकार द्वारा बालिका नामांकन में वृद्धि करने एवं बालिका साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए 850 अतिरिक्त महिला अध्यापिकाओं के पद उपलब्ध कराये गये हैं।

वर्तमान में कुल 27,558 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिनमें से 26,104 विद्यालय छात्रों के तथा 1,454 विद्यालय छात्राओं के हैं।

इस वर्ष के अन्त तक 6–11 आयु-वर्ग के 43 लाख बच्चों को नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया था इसके विपरीत लक्ष्य से भी अधिक 44·01 लाख बच्चों को नामांकित किया जा चुका है। यह हर्ष का विषय है कि बालिका नामांकन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई है।

उच्च प्राथमिक शिक्षा

उच्च प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए आलोच्य वर्ष में सुनियोजित प्रयास किए गये हैं। 1,550 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। इनमें 1,351 छात्रों तथा 199 छात्राओं के विद्यालय हैं। 1,500 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में तथा 50 विद्यालय शहरी क्षेत्र में खोले गये हैं। छात्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,307 तथा 193 छात्राओं के विद्यालय खोले गये। इसके विपरीत शहरी क्षेत्र में छात्रों के 44 एवं 6 छात्राओं के विद्यालय खोले गये हैं।

वर्ष 1983–84 मे खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 7—8 के लिए 1,303 अध्यापक उपलब्ध कराये गये हैं।

वर्तमान में 7,950 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं इनमें से 6,855 छात्रों के तथा 1,095 छात्राओं के विद्यालय हैं।

11–14 आयु-वर्ग में इस वर्ष के अन्त तक 10·90 लाख बच्चों को नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध 11·09 लाख बच्चों को नामांकित कर लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा

9–14 आयु-वर्ग के बहुत से ऐसे बालक और बालिकाएँ हैं जो सामाजिक,

आर्थिक और पारिवारिक स्थिति के कारण औपचारिक विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश बच्चे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिवार की आर्थिक दशा को सुधारने में योगदान देते हैं। इन्हें शिक्षा प्रदान करने का अनौपचारिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए नये 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 में सम्मिलित किया गया।

वर्ष 1984–85 में 10,600 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिनके लिए नामांकन लक्ष्य 3·92 लाख रखा गया है। इन केन्द्रों के माध्यम से माह फरवरी, 1985 तक 3·37 लाख बालक–बालिकाओं को लाभान्वित किया गया जिनमें 1·80 लाख बालक तथा 1·57 बालिकाएं हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति के 39,666 बालक तथा 35,699 बालिकाओं के साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के 41,439 बालक तथा 30,377 बालिकायें लाभान्वित हो रही हैं।

राज्य में 3,000 बालिकाओं के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। राजस्थान में 15 स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 560 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन भारत सरकार के अनुदान से किया जा रहा है तथा शेष केन्द्र भारत सरकार से 50 प्रतिशत एवं राज्य सरकार से 50 प्रतिशत अनुदान से संचालित किए जा रहे है।

यह प्रसन्नता की बात है कि अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिका नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति पर वर्ष 1983–84 में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार के रूप में भारत सरकार द्वारा 30 लाख रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई है। वर्ष 1984–85 में भी बालिका नामांकन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य हेतु राज्य सरकार को 25 लाख रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के विकास को गति देने के उद्देश्य से 395 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। इनमें से शहरी क्षेत्र में 35 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 360 विद्यालय खोले गये। छात्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 338 तथा छात्राओं के लिए 22 विद्यालय खोले गये।

शहरी क्षेत्र में छात्रों के लिए 18 तथा छात्राओं के लिए 17 विद्यालय खोले गये हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस वर्ष प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

इसी वर्ष 99 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया है।

इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 64 छात्रों के तथा 9 छात्राओं एवं शहरी क्षेत्र में 9 छात्रों के तथा 17 छात्राओं के विद्यालय खोले गये हैं।

इस प्रकार इस सत्र में कुल 2,052 माध्यमिक तथा 892 उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं। माध्यमिक विद्यालयों में से छात्रों के 1,791 तथा 261 छात्राओं एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 742 छात्रों के तथा 150 छात्राओं के विद्यालय हैं।

माध्यमिक शिक्षा में उर्दू विषय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 84–85 में 100 उर्दू अध्यापकों के पद भी सृजित किये गये।

माध्यमिक शिक्षान्तर्गत विषय/वर्ग की अधिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 356 वर्ग एवं 87 विषय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खोले गये हैं।

छात्रवृत्ति

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रदत्त राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना इस वर्ष भी जारी रही। इस वर्ष में इस योजनान्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति से 3 सामान्य, 2 भूमिहीन, 1 अनुसूचित जाति, 1 अतिरिक्त छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति छात्र को जहां की पंचायत समिति के क्षेत्र में 20% एस.. सी. की जनसंख्या हो एवं 3 जनजाति छात्रों को अतिरिक्त छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। इस प्रकार इस योजना में करीब 17 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां स्वीकृता की गई हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों में प्रवेश हेतु 15 लाख रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। इसी वर्ग के छात्रों को

साधारण छात्रवृत्ति के अन्तर्गत करीब 1 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गये हैं।

जनजाति उपयोजनान्तर्गत प्रतिभावान छात्रों को इस वर्ष 1·38 लाख रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। इसी वर्ग में विज्ञान एवं गणित संकाय के छात्रों के अध्ययन हेतु 3·65 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

इस वर्ष संस्कृत ऐच्छिक विषय लेकर अध्ययन करने वाले छात्रों हेतु राज्य में 300 छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की गई हैं। अत्यन्त निर्धन छात्रों के लिए 30000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, शिक्षा सामग्री एवं पोशाक तथा बालिकाओं को प्राथमिक स्तर पर उपस्थिति छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस प्रकार इस योजनान्तर्गत 3,32,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

शिक्षक पुरस्कार

इस योजनान्तर्गत 1984 में राष्ट्रीय स्तर पर 5 अध्यापकों को पुरस्कृत किया गया जिनमें 3 पुरुष एवं 2 महिलायें हैं। राज्य स्तर पर 21 पुरुष एवं 8 महिला अध्यापिकाओं सहित कुल 29 पुरस्कार दिए गये।

बाल प्रतिभाओं की पुरस्कार योजनान्तर्गत 10 विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर एवं 135 विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने हेतु पुरस्कृत किया गया।

पुस्तकालय

राजस्थान में पुस्तकालय सेवाओं में भी इस वर्ष काफी कार्य हुआ है। राज्य सरकार का प्रयत्न है कि जिन तहसीलों में और जिलों में सार्वजनिक पुस्तकालय अभी तक नहीं खोले जा सके हैं वहां शीघ्र ही खोले जायें। प्रयत्न यह भी चल रहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भी एक सार्वजनिक पुस्तकालय कायम हो।

वर्ष 1984–85 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों के लिए

पुस्तकालयाध्यक्ष के 86 पद सृजित किये गये हैं। प्रथम श्रेणी के : भी 1(पुस्तकालय अध्यक्षों के पद सृजित किए गए हैं।

राज्य स्तरीय केन्द्रीय पुस्तकालय जयपुर में भवन सम्बन्धी स समस्या की ओर भी राज्य सरकार ने ध्यान दिया है। भवन निर्माण हेतु 3 वर्षों में करीब 40 लाख रुपये व्यय करने की योजना है। भवन निर्माण कार्य आ आरम्भ हो चुका है तथा मार्च 85 तक 9 लाख 90 हजार रुपये व्यय किये जाने की सम्भावना है।

राज्य सरकार ने राज्य में पुस्तकों के विकास के लिए तथा पुस्तक निर्माण तथा वितरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "पुस्तक विकास परिषद" का गठन करके लेखकों एवं प्रकाशकों को इसका सदस्य बनाया है।

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय भावनात्मक एकता हेतु सामूहिक गायन कार्यक्रम के संचालन हेतु एक प्रशिक्षण शिविर द्वारा 200 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

योग शिक्षा व्यवस्था हेतु 4 प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 180 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्काउट गाईड आन्दोलन के अन्तर्गत प्रदेश में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग 20 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है। प्रदेश में इस समय 6 डिवीजनल ऐसोसियेशन एवं 178 स्थानीय ऐसोसियेशनों के अन्तर्गत स्काउट विभाग में 1,65,079 व गाईड विभाग में 33,623 सदस्य संभागी हैं।

राज्य सरकार इस आन्दोलन के माध्यम से देश में सुनागरिक एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है।

———

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा को नये 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 में सम्मिलित किया गया है। देश में तथा राजस्थान में जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तीन मुख्य आयाम हैं—(1) साक्षरता, (2) सामाजिक चेतना. (3) क्रियात्मकता। इन सभी क्षेत्रों की दृष्टि से वर्ष 1984-85 में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को द्रुत गति दी गई।

ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता योजना

इस वर्ष भारत सरकार द्वारा सौ प्रतिशत आर्थिक सहायता के आधार पर स्वीकृत 8,100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये गये। इन केन्द्रों को 300-300 केन्द्रों की 27 परियोजनाओं में संचालित किया गया। प्रत्येक जिले में एक परियोजना चलाई गई। 8,100 केन्द्रों में से 2,648 केन्द्र केवल महिलाओं के लिए चलाये गये। इन केन्द्रों से लाभान्वित होने वाले प्रौढ़ों की संख्या 2,36,497 रही जिनमें से 1,43,861 पुरुष तथा 92,636 महिलाएँ हैं। लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति के 52,998 तथा अनुसूचित जनजाति के 37,551 प्रौढ़ हैं।

राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष 84-85 में राजस्थान सरकार के व्यय पर 3,400 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये जो 14 जिलों में कार्यरत हैं। इन 3,400 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों से 64,764 पुरुष एवं 39,031 महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित होने वाले प्रौढ़ों की संख्या क्रमशः 27,815 व 23,241 रही है।

स्वयं सेवी संस्थाएँ

राज्य की 13 स्वय सेवी संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा 490 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्वीकृत किये गये तथा इनके लिए वित्तीय सहायता भी भारत सरकार द्वारा दी गई। इन केन्द्रों से 8,703 पुरुष तथा 5,753 महिलायें लाभान्वित हुई हैं जिनमें से अनुसूचित जाति के 3,474 तथा अनुसूचित जनजाति के 2,253 प्रौढ़ हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं के अतिरिक्त 4 नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा 40 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये, जिनके माध्यम से 1,056 प्रौढ़ लाभान्वित हुए।

उत्तर साक्षरता कार्यक्रम

राज्य में 11 जिलों में भारत सरकार द्वारा सौ प्रतिशत अनुदान पर स्वीकृत 11 उत्तर साक्षरता की परियोजनाओं के माध्यम से 725 उत्तर साक्षरता केन्द्र संचालित किये गये। राजस्थान सरकार के व्यय पर 7 जिलों में उत्तर साक्षरता की 7 परियोजनाओं के माध्यम से 455 उत्तर साक्षरता केन्द्र चलाये गये। इन 1,180 उत्तर साक्षरता केन्द्रों से 26,533 पुरुष तथा 9,196 महिलाएँ लाभान्वित हुईं। इनमें अनुसूचित जाति के 7,840 तथा अनुसूचित जनजाति के 4,172 प्रौढ़ हैं।

महिला साक्षरता पुरस्कार योजना

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 83–84 में एक प्रोत्साहन एवं पारितोषिक योजना आरम्भ की गई। यह हर्ष की बात है कि वर्ष 82–83 में प्रदेश में महिला साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति करने के फलस्वरूप राज्य सरकार को 9·25 लाख रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 83–84 में भी महिला साक्षरता में विशिष्ट योगदान देने के कारण 84–85 में भी राज्य सरकार को पुन: 9·75 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

कक्षा 4 की नई पाठ्यपुस्तकें

राज्य सरकार ने प्राथमिक शालाओं के लिए नया पाठ्यक्रम स्वीकार किया है। इसके अन्तर्गत कक्षा 4 की पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण किया गया। ये पाठ्य-पुस्तकें जुलाई, 85 से राज्य में कक्षा 4 में चलने लगेंगी। इससे पूर्व कक्षा 3 तक की नई पाठ्य-पुस्तकें निर्मित की जा चुकी हैं।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं का नया पाठ्यक्रम

प्राथमिक कक्षाओं का नया पाठ्यक्रम स्वीकार हो गया है अतः उच्च प्राथमिक कक्षाओं का नया पाठ्यक्रम इस वर्ष संस्थान द्वारा बनाया गया है।

प्राथमिक विद्यालय स्तर पर पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण स्वच्छता के अच्छे शिक्षण के लिए नया पाठ्यक्रम का भी निर्माण किया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा का विस्तार

इस वर्ष अनौपचारिक शिक्षा के नये केन्द्र खोले गये है और उनके लिए जो केन्द्र पुराने चल रहे हैं उन सभी के लिए पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कराई गई और 8 लाख पुस्तकें राज्य में नि:शुल्क वितरित की गई हैं। जरूरतमन्द बालक बालिकाओं को अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए और उनकी भली प्रकार से व्यवस्था के लिए परिवीक्षण अधिकारी अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित किये जाने वाले परिवीक्षण कार्यकर्ताओं की संख्या 110 और अनुदेशकों की संख्या 3,000 थी। यह संख्या उन्हीं लोगों की है जो इस कार्यक्रम में इस वर्ष नये जुड़े हैं। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर बालकों को उपयोगी शिक्षा दी जा सके इसके लिए साहित्य का निर्माण किया गया है। यह साहित्य उन्हीं की आवश्यकता और परिवेश को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो लगभग 500 घंटे का है। इस साहित्य से बालक/बालिकाओं की शिक्षा में रुचि बढ़ेगी और लाभ होगा।

बालकों को रोजगार कार्यक्रम की जानकारी

बालकों को रोजगारों के बारे में जानकारी देने के लिए 6 जिला स्तरीय समारोह आयोजित किये गये जिसमें 22,240 छात्रों ने भाग लिया। विद्यालयों में छात्रों को रोजगारों की जानकारी मिलती रहे और उनकी समस्या हल हो इसके लिए 450 अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

विकलांग बालकों की शिक्षा

विकलांग बालकों को भली प्रकार से शिक्षा दी जा सके और लोगों की इसमें रुचि बढ़े इसके लिए एक फिल्म का निर्माण किया गया, 38 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकें। प्रशिक्षण में इस बात पर बल दिया गया कि विकलांग बालक बालिकाओं की शिक्षा किस प्रकार व्यवसाय से सम्बद्ध हो सकती है।

प्राथमिक शिक्षा का उन्नयन

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का स्तर सुधरे इसके लिए ग्रीष्मावकाश में और अन्य दिनों में 60 शिविर आयोजित किये गये हैं। इन शिविरों में लगभग 2000 अध्यापक लाभान्वित हुए हैं। इन शिविरों में एकल अध्यापकी शालाओं के अध्यापकों ने भी भाग लिया। आशा है इस शिविर में सभी विषयों के शिक्षण से अध्यापक अपने विषयों के ज्ञान की कमी पूर्ति कर छात्रों को लाभान्वित कर सकेंगे।

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी समस्याओं के बारे में खुद विचार करें और खुद हल करें इसके लिए जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय पत्रवाचन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में पिछले वर्ष की तुलना में 1½ गुना अधिक अध्यापकों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता

सामूहिक गायन हेतु देश के विभिन्न भागों के और विभिन्न भाषाओं के गीतों का 245 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। अध्यापकों को इन गीतों के केसैट और टेपरिकार्डर भी दिये गये ताकि वे अपने विद्यालयों में इन गीतों के माध्यम से विद्यालयों में राष्ट्रीय भावात्मक एकता का प्रसार कर सकें। छात्रों ने राष्ट्रीय दिवसों पर इन गीतों का सामूहिक प्रदर्शन भी किया।

अनुसंधान कार्य

विभिन्न जिलों में 15 अनुसंधान कार्यों को स्वीकार किया गया। संस्थान स्तर पर अधिकारों के विकेन्द्रीकरण से संबंधित अध्ययन किया गया।

जनसंख्या शिक्षा योजना

जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संस्थान स्तर पर कई कार्य किये गये। कक्षा 3 से 8 तक जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। जनसंख्या शिक्षा विद्यालयों में भली प्रकार दी जा सके इसके लिए शिक्षक संदर्शिकाएं बनाई गई। माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं की एवं पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया गया और उनमें जनसंख्या शिक्षा से संबंधित नई सामग्री देने के लिए कार्य किया गया। लगभग 10,000 अध्यापकों को जनसंख्या शिक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे छात्रों को जनसंख्या शिक्षा समस्याओं के बारे में भली प्रकार शिक्षा दे सकें। जनसंख्या शिक्षा से संबंधित उपयोगी साहित्य का भी प्रकाशन किया गया।

विज्ञान शिक्षा सुधार

विज्ञान शिक्षण में स्थानीय सामग्री का अधिकाधिक उपयोग हो और छात्रों को स्थानीय साधनों से विज्ञान में अच्छी शिक्षा दी जा सके इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान प्रतिभा के विकास के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर विज्ञान मेलों का आयोजन किया गया जिनमें छात्र/छात्राओं ने स्वप्रेरणा से नये-नये उपकरण बनाए और उनका प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में 381 बाल वैज्ञानिकों ने नये उपकरण प्रदर्शित किए। सामान्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े इसके लिए सामुदायिक विकास केन्द्र का संचालन किया गया। इससे वर्ष भर में लगभग 1 लाख लोग लाभान्वित हुए।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

राज्य में माध्यमिक शिक्षा पद्धति को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील रूप में विकसित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त, 1957 को की गई। इस प्रकार बोर्ड ने सन् 1984 तक अपने कार्यकाल के 27 वर्ष विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को सफलता पूर्वक संचालित करते हुए पूर्ण कर लिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में बोर्ड का रजत जयन्ती समारोह दिनांक 12-2-1984 को सम्पन्न हुआ।

प्रतिवेदित वर्ष 1984 में बोर्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निम्न विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित की गई हैं —

परीक्षा प्रणाली में सुधार

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु बोर्ड द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है। बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किये हैं जिनमें प्रश्नपत्रों में उद्देश्यनिष्ठ प्रश्नों का समावेश विज्ञान विषय के पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण एवं मूल्यांकन की नवीन विधि में अध्यापकों तथा प्रश्न-पत्र निर्माताओं का प्रशिक्षण आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं।

परीक्षा कार्य

बोर्ड का प्रमुख कार्य (1) सैकण्डरी, (2) हायर सैकण्डडरीडरी, (3 प्रवेशिका तथा (4) उपाध्याय परीक्षाओं का संचालन करना है।। । प्रतिव विभिन्न परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले छात्रों की संख्या में हो रही निररन्तरन्तर वृ को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित रूप में परीक्षा संचालन करना द बोर्ड व ध्येय रहा है । वर्ष 1983 में विभिन्न परीक्षाओं में कुल 3,,26,26,41 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे किन्तु सन् 1984 में यह संख्या बढ़कर 3,,5,51,25 हो गई । इस प्रकार गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष 24,842 छात्र परपरीक्षा अधिक बैठे । छात्रों की संख्या में हुई इस वृद्धि के उपरान्त भी सम्पूर्णर्ण परीक्ष कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न हुआ तथा सभी परीक्षा प परिणा जून, 1984 से पूर्व घोषित कर दिये गये ।

सन् 1985 की विभिन्न परीक्षाओं हेतु 3,96,659 छ्छात्रों क पंजीकरण हुआ है । परीक्षार्थियों की संख्या में हुई इस वृद्धि को दृष्टिगतगत रखते हुए परीक्षा केन्द्रों की संख्या 882 से बढ़ाकर 951 कर दी गई है ।

परीक्षार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं पदक तथा विद्यालयों को विजयोपहार

मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न परीक्षाओं में य योग्यता सूची के आधार पर प्रथम पांच/दस स्थान प्राप्तकर्ता को विभिन्न दरदरों पर छात्रवृत्तियां एवं प्रथम तथा द्वितीय रहने वाले छात्र छात्राओं को पदकक प्रदान किए गये । वर्ष 1984-85 में विभिन्न परीक्षाओं में योग्यता सूची के आधार पर वरीयता क्रम में 392 छात्र/छात्राओं को कुल रुपये 3,15,2500/- की छात्रवृत्ति प्रदान की गई । इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देन्देने वाले विद्यालयों को विभिन्न आधारों पर प्रतिवर्ष शील्ड्स भी प्रदान की जाताती है । अच्छे परिणाम देने वाले विद्यालयों को बोर्ड द्वारा भ्रमण अनुदान भीभी दिया जाता है ।

अध्यापक कल्याण कोष

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक संकटग्रस्त शिक्षकों और उनके आश्रितों को सहायता प्रदान की जाती है । इस कोष से 31-3-1984 तक एवं वर्ष में सेवारत/सेवानिवृत/दिवंगत अध्यापकों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 1,09,300/- रुपये स्वीकृत किये गये ।

पत्राचार पठ्क्रम

माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक विकास की दृष्टि से बोर्ड द्वारा हायर सैकण्डरी स्तर स्वयंपाठी छात्रों के लिए सन् 1968-69 से पत्राचार पाठ्य क्रम योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष कुल 16,080 छात्रों ने पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण करवाया। इन छात्रों को नियमित रूप से योग्य शिक्षकों द्वारा निर्मित पाठ उपलब्ध करवाये गये। पाठ उपलब्ध कराने के साथसाथ इस वर्ष 18 स्थानों पर सम्पर्क कार्यक्रम द्वारा छात्रों को अतिरिक्त शिक्षण भी प्रदान किया गया। पत्राचार पाठ लेखन कार्य के लिए इस वर्ष एक कर्यगोष्ठी का आयोजन कर अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बोर्ड द्वरा सैकण्डरी स्तर पर भी कुछ विषयों में पाठ तैयार करवाये गये हैं जो शाला एवं छात्र दोनों को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन एवं राष्ट्रीयकरण

बोर्डद्वारा पाठ्यपुस्तकें तैयार करने संबंधी नीति को नया रूप दिया गया है। जुलई, 1961 से ही पाठ्य पुस्तकें बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखक/लेखकों द्वारा तैयार हो जाती रही हैं। इस नीति के माध्यम से बोर्ड पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयाकरण हेतु वचनबद्ध है। पुस्तकों की समीक्षा विधि में भी सुधार किया गया है तथा प्रत्येक विषय की पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए व्यापक मापदण्ड तैयार किया गया है। अब तक विभिन्न विषयों में 85 पुस्तकें बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखकों से तैयार करवाई जाकर शालाओं में लागू की जा चुकी है। आलोच्य वर्ष में बोर्ड ने 10 पुस्तकों का मुद्रण तथा वितरण भी अपने हाथ में ले लिया है। वर्ष 1984-85 के दौरान सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, 1986 हेतु नौ विषयों एवं हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1985 हेतु आठ विषयों में पाठ्यक्रम में परिवर्तन व सुधार किये गये हैं। तदनुसार विभिन्न विषयों की कुल 44 पुस्तकों के संशोधित सस्करण तैयार किये गये।

शैक्षिक कार्यक्रम

(अ) प्रश्नपत्र विश्लेषण

प्रशपत्रों का स्तर अच्छा बनाये रखने की दृष्टि से बोर्ड द्वारा निर्धारित

मापदण्डों के आधार पर सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी परीक्षा प्रश्नपत्रों का विषय विशेषज्ञों से विश्लेषण कराया जाता है। इस वर्ष सैकण्डरी परीक्षा के 29 तथा हायर सैकण्डरी परीक्षा के 23 प्रश्नपत्रों का विश्लेषण कार्य करवाया गया।

(ब) प्रश्नकोष तथा नमूने के प्रश्न पत्रों का निर्माण

पाठ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से विभिन्न विषयों में प्रश्न कोष निर्माण का कार्य विगत कुछ वर्षों से किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष दो विषयों में प्रश्नकोष का मुद्रण करवाकर विद्यालयों एवं छात्रों को उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही अन्य तीन विषयों में भी प्रश्नकोष शीघ्र ही मुद्रित कर उपलब्ध करवाये जावेंगे। इस वर्ष छ: विषयों में नमूने के प्रश्न-पत्रों का निर्माण भी करवाया गया है, तथा इन्हें भी शीघ्र मुद्रित करवाकर विद्यालयों को नि:शुल्क भेजा जावेगा।

(स) न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों का निरीक्षण

वर्ष 1984 की सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी परीक्षा में न्यून परिणाम देने वाले 169 विद्यालयों में से 28 विद्यालयों का निरीक्षण करवाया गया और निरीक्षण प्रतिवेदन शिक्षा विभाग से सबन्धित परिवीक्षण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये।

(द) शोध प्रायोजनायें

(1) शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहन देने हेतु बोर्ड प्रति-वर्ष विद्यालयों से शोध परियोजनाएं आमंत्रित करता है तथा चयनित परियोजना प्रभारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड द्वारा रु० 500/- तक प्रति परियोजना की दर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इस वर्ष चयनित 20 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रथम किश्त (50%) के रूप में रुपये 3,330/- का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। परियोजनाएं पूर्ण होने पर शेष स्वीकृत राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।

(2) छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से संबन्धित परियोजना कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तैयार रिपोर्ट तथा समग्र मूल्यांकन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

(इ) कक्षा 9 तथा 10 के पाठ्यक्रम में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा विषय का समावेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में सैकण्डरी स्तर पर पाठ्यक्रम में एक नवीन विषय "समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाजसेवा" अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। यह विषय इस वर्ष कक्षा 9 में सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू कर दिया गया है। समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों में छात्रों की सहभागिता के फलस्वरूप उनमें सामाजिक एवं उत्पादक कार्यों के प्रति रुचि एवं अनुकूल अभिवृत्ति बन सकेगी तथा श्रम के प्रति निष्ठा एवं सकारात्मक रुझान विकसित होगा। इसके साथ ही उनमें परस्पर सहयोग एवं सहायता से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास भी होगा।

इसके सफल संचालन हेतु राज्य के समस्त जिलों के चयनित संस्था प्रधानों के 2 शिविर एन. सी. ई. आर. टी. के सहयोग से आयोजित किये गये जिनसे वे अपने जिले में संदर्भ व्यक्ति का कार्य कर अन्य को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे शिविर मंडल स्तर पर भी आयोजित किये गये। कार्यकारी दल द्वारा संदर्शिका तैयार की गई जो शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को मार्ग-दर्शन देने में लाभप्रद सिद्ध हुई है। शिविर प्रतिवेदन से विषय की उपयोगिता प्रमाणित हुई है।

(उ) पत्र वाचन प्रतियोगिता

अध्यापकों की शैक्षणिक रुचि को विकसित करने एवं उन्हें शैक्षणिक समस्याओं के प्रति जागरुक करने की दृष्टि से बोर्ड, 1975 से पत्र वाचन संगोष्ठियों का आयोजन करता रहा है। इस वर्ष 83 पत्र प्राप्त हुए तथा राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के आधार पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अध्यापकों को क्रमशः रुपये 300/- 150/- व 100/- छः क्षेत्रों में पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये गये। जिला स्तर पर भी रुपये 100/-, 60/-, 40/- की दर से पुरस्कार दिये गये।

(ऊ) आन्तरिक मूल्यांकन

इस वर्ष आन्तरिक मूल्यांकन संबन्धी 8 निर्देश पुस्तिकाओं के संशोधित संस्करण तैयार कराये गये। आन्तरिक मूल्यांकन प्रशिक्षण हेतु विभिन्न छः

स्थानों पर कार्यगोष्ठियाँ आयोजित कर 388 प्रभारी अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया ।

राज्य स्तरीय छात्र प्रतियोगिता बोर्ड द्वारा आयोजित की गई और चार प्रवृत्तियों में प्रत्येक से प्रथम व द्वितीय रहने वाले छात्र/छात्राओं को पदक प्रदान किये गये ।

(य) राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज

राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा संबंधी पाठ्यक्रम एवं आदर्श प्रश्न पत्र बनाने के लिए कार्यगोष्ठियाँ आयोजित की गई । समय से पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र उपलब्ध कराये गये और राज्य के लिए निर्धारित प्रथम 110.04 छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया ।

(र) प्रश्न पत्र निर्माता कार्यगोष्ठियाँ

विभिन्न विषयों में प्रश्न पत्र तैयार करने हेतु अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी बोर्ड द्वारा किया जाता है । इस वर्ष आठ विषय में कुल 78 अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया जो भविष्य अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण में सहायक होंगे ।

(ल) बोर्ड शिक्षण पत्रिका

सन् 196[illegible] से बोर्ड द्वारा एक त्रैमासिक शिक्षण पत्रिका प्रकाशित की जा रही है । इसमें शिक्षा से सम्बन्धित उच्च स्तरीय लेख प्रकाशित किये जाते हैं । वर्तमान में पत्रिका के लगभग 14,000 ग्राहक हैं । गत वर्ष ग्राहकों की संख्या 13,000 थी ।

आवासीय भवन सुविधा

विगत 20 वर्षों से बोर्ड द्वारा क्रय की गई भूमि पर कर्मचारियों के आवास गृह बनाना प्रथम बार आरम्भ किया गया है । इस सत्र में सचिव और 12 अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के आवास गृह निर्मित हो रहे हैं । बैठकों व कार्यगोष्ठियों में बाहर से आने वाले माननीय सदस्यों के लिये बोर्ड द्वारा एक विश्राम गृह और जलपान गृह भी इसी वर्ष निर्मित हो रहे हैं ।

———

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, राजस्थान में अविभक्त इकाई से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिये सस्ती, सुन्दर तथा अनद्यतन ज्ञान विज्ञान की समग्र सामग्री से युक्त पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं एवम् अध्यापक दर्शिकाओं के लेखन, संशोधन, मुद्रण एवम् वितरण व्यवस्था में संलग्न स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान है जो गत 29 वर्षों (1956) से निरन्तर अपने दायित्व निर्वहन के प्रति तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूर्णतः सन्नद्ध है। यह मण्डल प्रदेश के सभी विद्यालयों व महाविद्यालयों में चेतक अभ्यास पुस्तिकाओं के वितरण का दायित्व निर्वाह भी करता है।

प्रतिवेदनाधीन (1984-85) वर्ष में मण्डल ने कुल 70 पुस्तकों के मुद्रण की योजना अपने हाथ में ली है, जिनमें अविभक्त इकाई से कक्षा 5 तक की 14 पुस्तकें, कक्षा 6 से 8 तक की तीस पुस्तकें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद् द्वारा रचित विज्ञान विषय की सात पुस्तकें, अनौपचारिक शिक्षा की पाँच पुस्तकें, प्रौढ शिक्षा की दो पुस्तकें, अंग्रेजी वर्क बुक कक्षा 6 व 8, अध्यापक संदर्शिका अंग्रेजी कक्षा 7 व 8, सिन्धी अरेबिक भाषा की 6 पुस्तकें, उर्दू भाषा की एक पुस्तक तथा यूनिसेफ की विज्ञान विषय की एक पुस्तक सम्मिलित है।

इन पुस्तकों में शिक्षा के परिवर्तित राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित प्राथमिक शिक्षा के नवीन पाठ्यक्रमानुसार लिखित चार परिवर्तित पाठ्य पुस्तकों की पाण्डुलिपियों के अनुसार नवीन पुस्तकों तथा अंग्रेजी की दो कार्य पुस्तिकाओं व दो अध्यापक संदर्शिकाओं का नवीन रूप में मुद्रण भी शामिल है।

मण्डल के दायित्व निर्वहन एवं कार्य संचालन हेतु शासी परिषद् एवम् निष्पादक परिषद् का गठन किया गया हैं। शासी परिषद् मण्डल की प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षिक एवम् विकास सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण करती है तथा निष्पादक परिषद् उपर्युक्त नीतियों का क्रियान्वयन व अनुपालन करती है। मण्डल के दैनिक एवम् नियमित कार्य संचालन हेतु निष्पादक परिषद् के सभापति व सचिव उत्तरदायी हैं।

पुस्तक वितरण व्यवस्था

प्रदेश में बढ़ती हुई छात्र संख्या को मद्येनजर रखते हुये राज्य सरकार

ने मण्डल के 37 वितरण केन्द्रों में वृद्धि कर कुल 44 वितरण केन्द्र खोल दिये हैं जिनमें से दस जोनल तथा 34 सामान्य वितरण केन्द्र हैं।

पुस्तकों की बिक्री

प्रतिवेदित वर्ष 1984-85 में (माह फरवरी 1985 तक) 94,400,831 पुस्तकें 2,69,53,295.96 रुपयों की राशि की बेची गई हैं। उपर्युक्त वितरण केन्द्र विद्यालयों को 15% कमीशन काटकर तथा पंजीयत पुस्तक विक्रेताओं को 12.5% कमीशन पर पुस्तकें सप्लाई करते हैं।

अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण

सत्र 1980–81 से पूर्व तक राजस्थान में नियंत्रण मूल्य की चेतक अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण कापी निर्माताओं द्वारा सीधा ही विद्यार्थियों को किया जाता था, किन्तु इसके बाद से राज्य सरकार के आदेशानुसार इन अभ्यास पुस्तिकाओं के वितरण का दायित्व भी मण्डल को सौंपा गया। प्रतिवेदित वर्ष में मण्डल ने अपने वितरण केन्द्रों के माध्यम से 1,40,04,445.15 रुपयों की राशि की अभ्यास पुस्तिकायें विक्रय की गई है। वर्तमान में मण्डल के पास अस्सी लाख रुपयों की अनुमानित राशि की अभ्यास पुस्तिकाएँ अग्रिम सत्र के लिये सुरक्षित हैं।

भवन सम्बन्धी प्रगति

इस वर्ष मण्डल का अपना निजी भवन भी निर्माणाधीन है, जिसमें कुल एक करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस समय तक भवन में पैंतीस लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

पुस्तकें समय पर उपलब्ध हों इस हेतु निष्पादन परिषद् ने निर्णय लिया है कि मुद्रण वर्ष 1986 के लिये छपाई जाने वाली पुस्तकों के मुद्रण की प्रारम्भिक कार्यवाही माह मई 1985 से ही आरम्भ कर दी जाये।

मण्डल का सदैव यही प्रयास रहा है कि राजस्थान के उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों, अनौपचारिक एवम् प्रौढ शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययनरत व्यक्तियों को अद्यतन नवीन ज्ञान से युक्त सस्ती पुस्तकें तथा राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिये चेतक अभ्यास पुस्तिकाएँ आसानी से सुलभ हों।

———

संस्कृत शिक्षा

राज्य में संस्कृत के प्रचार प्रसार एवं शास्त्रीय अध्ययन, प्रशिक्षण व शोध संचालन की दृष्टि से 1958 में संस्थापित संस्कृत शिक्षा विभाग के तत्वावधान में वर्तमान में राजकीय संस्थायें 197 (आचार्य कालेज 3, शास्त्री कालेज 9, उपाध्याय विद्यालय 6+13, प्रवेशिका विद्यालय 30, संस्कृत उच्च प्राथमिक 70, संस्कृत प्राथमिक 64, तथा संस्कृत एस० टी० सी० 1) एवं अनुदानित व मान्यता प्राप्त संस्थाएं 135 (आचार्य कालेज 13, शास्त्री कालेज 6, शिक्षा-शास्त्री कालेज 3, उपाध्याय विद्यालय 14+17, प्रवेशिका विद्यालय 15, संस्कृत उच्च प्राथमिक 76, संस्कृत प्राथमिक विद्यालय 28) तथा 3 छात्रावास चल रहे हैं। इनमें कुल छात्र छात्राओं की संख्या 68,400 है जिनमें छात्राएं 16,800 व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं की संख्या 8,400 है।

वित्तीय वर्ष 1984-85 में छात्र संख्या में 16% की वृद्धि हुई है। राज्य के जिन क्षेत्रों में संस्कृत विद्यालय नहीं थे अथवा कम थे उनमें 50 उच्च प्राथमिक स्तर के नये विद्यालय खोले गये तथा 5 प्रवेशिका स्तर के विद्यालय एवं उपाध्याय स्तर का विद्यालय, आचार्य स्तर का कालेज क्रमोन्नत किया गया एवं शास्त्री स्तर के कालेज को तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय को निजी प्रबन्ध से राज्याधीनता में लिया गया।

विभाग के अधीन उपाध्याय स्तर के विद्यालयों में 20 नये विषय खोले गये एवं 6 अनुदानित संस्थाओं के अनुदान प्रतिशत में वृद्धि की गई।

राजकीय संस्कृत कालेज कालाडेरा में प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन का जन सहयोग से निर्माण कराया गया तथा सरमथुरा एवं पावटा में प्राथमिक स्तर के लिये ग्राम पंचायत से भवन आवंटित कराये गये।

उच्च शिक्षा

राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से लेखनीय सुधार एवं प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है।

वर्ष 1984–85 में उच्च शिक्षा में सभी दिशाओं में प्रगति हुई है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नतः प्रस्तुत है

संख्यात्मक विस्तार

इस वर्ष राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 63, व्यवसायिकक शिक्षण संस्थाओं की संख्या 19, अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की संख्या 46 असहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की संख्या 22 रही। विश्वविद्याललयों की संख्या 3, विश्वविद्यालय मानी गई संस्थान 2 (वनस्थली विद्यापीठ एवं पिलानी) एवं विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों की संख्या 6 रही। इस प्रकारार शिक्षा के लिए कुल संस्थाएं 161 रहीं।

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 1,68,345 सेसे बढ़कर 1,71,600 हो गई। इसमें राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या 78,49 से बढ़कर 80,500 हो गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों ककी संख्या 16,502 से बढ़कर 17,000 हो गई। यह तथ्य उच्च शिक्षा के विस्स्तार एवं समाज के पिछड़े वर्ग में उच्च शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने के सरकारररी प्रयत्न की सफलता का प्रतीक है।

पिछडे वर्ग में उच्च शिक्षा सुलभ कराने के क्रम में जन जातिति क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा में स्नातकोतर स्तर पर हिन्दी आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विषय तथा राजकीय महाविद्यालय,, डूंगरपुर में हिन्दी व समाज शास्त्र विषय प्रारम्भ किये गये। इस वर्ष राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर में स्नातक (कृषि) संकाय, राजकीय माहाविद्यालय सिरोही में विधि तथा कन्या महाविद्यालय, बीकानेर में स्तानक (गृहह विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये गये। इन व्यवसायिक विषयों के अलावा राजककीय महाविद्यालयों में 37 विषय स्नातक स्तर पर तथा 9 बिषय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में खोले गये।

गुणात्मक प्रगति

संकाय सुधार योजना के अन्तर्गत 100 शिक्षकों को अग्रिम अध्ययन हेतु एम० फिल० की सुविधा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से प्रदान की गई। विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय स्तर पर हुई संगोष्ठियों में शिक्षकों को भिजवाया गया। राज्यों में योग्य एवं निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायताा देने हेतु 10 प्रतिशत छात्रों को पूर्ण शुल्क एवं 10 प्रतिशता छात्रों को अर्द्ध शुल्क मुक्ति

के अतिरिक्त 4.50 लाख रुपये की छात्रवृतियां प्रदान करने का प्रावधान किया गया है ।

वर्ष 1984–85 में उच्च शिक्षा हेतु निम्न राशि का प्रावधान किया गया है :—

संस्था का प्रकार	बजट लाख रुपयों में		
	आयोजना भिन्न	आयोजना मद	योग
विश्वविद्यालय	1,082·76	50·00	1132·76
राजकीय महाविद्यालय	1,217·73	209·60	1,427·33
अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान	326·26	15·40	341·66

इस वर्ष नये विषय व प्रयोगशालायें, पुस्तकालय व कक्षाओं के कमरों का निर्माण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से राज्य सरकार द्वारा 50·00 लाख रुपये का प्रावधान किया है । जिसमें 25·80 लाख रुपये भवन मद में व 23·20 लाख रुपये नये विषयों में अतिरिक्त संकाय, वेतन, पुस्तकालय व विज्ञान उपकरण खरीदने हेतु प्रावधान किया है । साथ ही 1·00 लाख रुपया ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु प्रावधान किया गया है जो उर्दू विषय लेकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं । इस वर्ष उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा 38·00 लाख एवं केन्द्र सरकार द्वारा ?·50 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त 22·00 लाख रुपयों का प्रावधान राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति हेतु किया गया है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 7·20 लाख रुपये राशि का प्रावधान किया गया है । जिसमें 14,000 विद्यार्थी भाग लेंगे । प्लानिंग फोरम योजना के अन्तर्गत 10 महाविद्यालयों को 1·00 लाख रुपये का प्रावधान है ।

राजस्थान विश्वविद्यालय

कई वर्षों के बाद गत वर्ष विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र नियत समय पर शुरू हुआ । परीक्षाएँ निर्धारित तिथियों पर सम्पन्न हुईं, परीक्षा परिणाम

समय पर घोषित किये गये। 1984–85 का सत्र 7 जुलाई को प्रारम्भ किए जाने पर सभी क्षेत्रों में संतोष व्यक्त किया गया था।

शैक्षणिक क्षेत्र में विश्वविद्यालय की महाविद्यालय विकास परिषद ने शैक्षणिक समितियों से स्वीकृत कराकर निम्न पाठ्यक्रमों को सम्बद्ध महाविद्यालयों में लागू किया है—भेड़ और ऊन, वस्त्र शिल्प, पशुधन एवं चमड़ा, वन स्रोत एवं उनका उपयोग, पशुधन एवं दुग्धशालाएँ, ग्रामीण विकास व स्वास्थ्य एवं जन संख्या।

महाविद्यालय विकास परिषद के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से महाविद्यालयों को सहायतार्थ 233 लाख रुपये दिए गए। सम्बद्ध महाविद्यालयों की उच्च शिक्षा हेतु 159 फैलोशिप एम० फिल० और 35 फैलोशिप डाक्टर की उपाधि के लिए सुविधाएँ दी गई। समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कक्षाएँ आयोजित करने हेतु 4·16 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति में प्रगति भी उल्लेखनीय रही। जहाँ पहले ओवरड्राफ्ट की स्थिति रहती थी वहां 31 मार्च, 1984 को लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपये की बचत की स्थिति आई।

1983 में स्नातक स्तर की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन जयपुर में केन्द्रित कर लगभग 8000 परीक्षकों से तत्परता से इस कार्य को पूर्ण कराके उन्हें उक्त कार्य के पारिश्रमिक का तत्काल भुगतान भी कर दिया गया। 1984 परीक्षा के लिए भी यही प्रणाली अपनाई गई। परीक्षा और गोपनीय विभागों को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार ने अतिरिक्त प्रशासनिक पद सृजित किये। 1984 की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन के लगभल 95 प्रतिशत परीक्षाफल नवम्बर 1984 तक सम्पन्न कर दिये गये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्न पदों में एक करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है :—

1.	कार्मिक	12 लाख रुपये
2.	शैक्षणिक भवन एवं कार्मिक आवास	28·50 ,,
3.	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	19·60 ,,
4.	साज सज्जा	26·60 ,,
5.	विविध	19·95 ,,

विश्वविद्यालय को पर्यावरण तथा जनसंख्या अध्ययन के एक केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति मिल गई है।

संघलोक सेवा के 33वें प्रतिवेदन से यह बात हुई है कि राजस्थान विश्वविद्यालय भारत के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में घोषित योग्य प्रत्याशियों की अधिकतम संख्या के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए इसका स्थान दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद आता है।

जोधपुर विश्वविद्यालय

जोधपुर विश्वविद्यालय के लिये यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि सत्र 1983–4 (वित्तीय वर्ष 1984–85) में सभी परीक्षायें समय पर प्रारम्भ हुई एवं उनके परिणाम भी समय–सारिणी के अनुसार घोषित किये गये तथा 1984–85 सत्र की कक्षायें समय पर सुचारू रूप से शुरू हो गई।

आलोच्य सत्र में विश्वविद्यालय में एक वर्षीय पोस्ट-ग्रेज्यूएट कम्प्यूटर पाठ्यक्रम भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त प्रयास से शुरू कियागया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बीस लाख रुपये स्नातक स्तर की शिक्षा के विकास की योजना हेतु प्रदान किये। इसी प्रकार विश्वविद्यालय का रसायन शास्त्र विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा एवं शोध कार्य के विकास हेतु चयनित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 41.20 लाख रुपये विशेष अनुदान के रूप में स्वीकृत किये गये।

वार्षिक योजना 1983–84 के अन्तर्गत 20 लाख रुपये सामान्य शिक्षा एवं 7 लाख रुपये तक्नीकी शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा एवं शोध कार्य के विकास हेतु प्रदत्त किये गये।

विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिये वर्ष 1983 के परसनल प्रमोशन स्कीम

लागू की गई। जिसके फलस्वरूप लम्बी सेवारत लेक्चररों तथा रीडरों की क्रमशः रीडर तथा प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई। इसका शिक्षक वर्ग ने हार्दिक स्वागत किया।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर

विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने एवं प्रतिभा पलायन को रोकने की दृष्टि से शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियाँ करने का एक अभियान सा चलाया गया और इसके अन्तर्गत हजारों प्रत्याशियों का साक्षात्कार करके अब तक 659 प्राध्यापकों को स्थाई नियुक्तियाँ दी गई हैं जिसमें 47 प्रोफेसर, 159 एशोसिएट प्रोफेसर और 429 सहायक प्रोफेसर एवं 24 अन्य अधिकारी हैं। इन नियुक्तियों में वर्ष 1984–85 में कुल 60 शिक्षकों को स्थाई नियुक्ति दी गई इस न्यूनतम अवधि में इतनी अधिक नियुक्तियां करना देश के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक कीर्तिमान है। वर्ष 1984–85 में एक्स केडर प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत भी इस विश्वविद्यालय मे सर्वाधिक प्राध्यापकों की पदोन्नति हुई हैं।

यह वर्ष विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा बहिष्कार की प्रवृत्ति, शैक्षणिक सत्र में अनियमितता एवं अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के भविष्य पर जो प्रश्न-चिन्ह लगा हुआ था वह स्थिति शनैः-शनैः इस वर्ष अब समाप्त हो गई है। शैक्षणिक सत्र समय पर आरम्भ हुआ और विश्वविद्यालय परीक्षाएं बिना किसी गतिरोध के स्वतंत्र वातावरण में चल रही हैं। विभिन्न संकायों के शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के शान्तिमय वातावरण से प्रभावित होकर राज्य सरकार ने इस वर्ष भी पी. एम. टी. परीक्षाएँ संचालित करने का उत्तरदायित्व इस विश्वविद्यालय को सोंपा है। यही नहीं विश्वविद्यालय की कुशल संचालन व्यवस्था एवं प्रवन्ध दक्षता को ध्यान में रखकर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएँ

आयोजित करनेके लिए विश्वविद्यालय में परीक्षा केन्द्र स्थापित करने का निर्णय भी इसी वर्ष लिया है। प्रशासनिक एवं अन्य सेवाओं के लिए नियुक्ति पूर्व लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं के प्रशिक्षण हेतु छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण देने का कार्य भ पत्राचार पाठ्यक्रम महाविद्यालय ने इस वर्ष से चालू किया। इन प्रशिक्षणों मे विशेष रूप मे अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने का उद्देश्य है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने केन्द्र एवं राज्य स्तर के अनुसूचित एवं जनजाति विभाग से अनुदान प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इन वर्गों केअलावा सामान्य वर्ग के छात्रों को भी लाभ मिले इसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। अब तक इस विश्वविद्यालय में एक भी विषय में एम. फिल. को सुविधा नहीं थी परन्तु अब 8 विषयों में यह सुविधा उपलब्ध है।

आज की परिस्थितियों में कुशलतम प्रशासन प्रबन्ध बनाये रखने और उच्च स्तरीय सेवाओं में विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से वाणिज्य संकाय के अधीन जो एम. बी. ए. कार्यक्रम आरम्भ किया गया था इस प्रोग्राम के दूसरे बैच मे इस वर्ष अपना कार्यकाल पूरा किया।

इस वर्ष मौलिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय महाविद्यालयों को विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों के आधार पर 3 अलग-अलग कालेजों में विभाजित कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप इन संकायों के विकास की प्रबल संभावनाएं बन गई हैं एवं इनके कार्य में भी दक्षता बढ़ेगी।

नये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के गठन के साथ-साथ विश्वविद्यालय में कृषि एवं गैर कृषि संकायों के विकास की गति में किसी प्रकार की बाधा न आवे इस दृष्टि से इन दोनों के लिए दो अलग-अलग विद्वत परिषदों (एकेडेमिक कौंसिल) का गठन किया गया है। इस प्रकार इन दोनों संकायों के लिए अलग-अलग अधिष्ठाता परिषदों एवं स्नातकोत्तर परिषदों का भी गठन किया गया है। कृषि अनुसंधान के साथ-साथ पशुपालन अनुसंधान कार्य को भी पर्याप्त महत्व प्रदान करने की दृष्टि से अलग से निदेशालय (पशुपालन) के प्रयत्नों से कुछ पशुपालन फार्म भी विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित किए गये है तथा निकट भविष्य में और भी पशुपालन फार्म विश्वविद्यालय को मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं।

इस वर्ष विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की पदोन्नति "एक्स केडर" योजना लागू की गई पी. एम. टी. परीक्षा परिणाम भी समय से पूर्व ही

घोषित किए गये। यही नहीं विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने में छात्रों ने भी सशक्त भूमिका निभाई।

इस वर्ष विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय के सेवाकाल में असामयिक निधन अथवा गम्भीर बीमारी या निर्योग्य अवस्था में आर्थिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय का अध्यापक एवं शैक्षणेत्तर कल्याण न्यास गठित किये गये हैं।

अनुसंधान कार्य के परिणामों को कृषकों तक पहुंचाने के उद्देश्य को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से विस्तार निदेशालय के अन्तर्गत प्रदेश के 13 जिलों में कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापित किए गये हैं। निदेशालय प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशनों आदि के माध्यम से कृषकों, कृषक महिलाओं एवं युवकों तक नई कृषि विधियाँ पहुँचाता है साथ ही प्रसार के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एवं बैंक अधिकारियों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है जिससे वे अधिक प्रभावी तरीके से वैज्ञानिक उपलब्धियों को उनके उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकें।

कृषि विस्तार के सक्रिय क्रिया-कलापों का प्रत्यक्ष परिणाम देखकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बांसवाड़ा एवं बीचवाल (बीकानेर) में दो नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्वीकृति इस वर्ष दी है।

शिक्षा एवं शोध की क्रियाओं को त्वरित गति देने और निष्पादन को सही क्रियाएँ खोज निकालने की दृष्टि से विश्वविद्यालय में समय-समय पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक कार्यशालाएँ तथा गोष्ठियाँ आयोजित की गई, जिनमें देश एवं प्रदेश के कई प्रबुद्ध एवं अनुभवी शिक्षा शास्त्रियों एवं वैज्ञानिकों ने भाग लेकर अपने विचारों से नई दिशा निर्धारित की। इनमें रबी तिलहनों की राष्ट्रीय स्तरीय वार्षिक कार्यशाला, अखिल भारतीय समन्वित सस्य परियोजना की 15वीं वार्षिक कार्यशाला तथा शुष्क खेती पर क्रियात्मक प्रशिक्षण शिविर प्रमुख हैं। विस्तार निदेशालय में संचार कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों में कार्यरत 24 विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसी प्रकार अनाज एवं दालों की सस्योत्तर तकनीकी विकास पर एक अखिल भारतीय स्तर की कार्यशाला भारतीय कृषि मंत्रालय के विस्तार निदेशालय के सौजन्य से आयोजित की गई।

कृषि शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा

ने चने की नई किस्म आर. एस. जी. 44 की पहचान की है। आधा मीटर ऊँचाई वाली एवं 135 से 150 दिन में पक कर तैयार होने वाली इस किस्म की औसत उपज लगभग 20-22 क्विंटल प्रति हेक्टर है। इसी प्रकार ग्वांर की एक नई सुधरी किस्म दुर्गा बहार विकसित की गई है जिसमें फलियों की औसत लम्बाई 13 सेंटीमीटर हैं और फलियों की पहली तुड़ाई बुआई से लगभग 45 दिन बाद की जाती है। इस पर 5–6 बार तुड़ाई सम्भव है और हरी फलियों एवं बीज की उत्पादन क्षमता क्रमश: 50–60 एवं 5–6 क्विंटल प्रति हैक्टर है॥ कृषि अनुसंधान केन्द्र बोरखेड़ा (कोटा) पर धान की नई बौनी तथा सुगन्धित किस्म बी के-79 विकसित की गई है। बासमति के गुणों वाली इस किस्म की उत्पादन क्षमता लगभग 50–55 क्विंटल प्रति हैक्टर है व 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है।

प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा, जैव गैस एवं पवन शक्ति जैसे प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के विकास एवं उनकी उपयोगिता विधि को सामान्य जनमानस तक पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सौर चुल्हे एवं सौर ऊर्जा से वनस्पति एवं अनाज सुखाने के यन्त्र विकसित करने के उद्देश्य से परियोजना स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्राकृतिक ऊर्जा विभाग एवं राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के समन्वय से इस महाविद्यालय में एक केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके अधीन प्रदेश के विभिन्न भागों में 50 पवन पम्प लगाने का प्रावधान है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत की जानकारी सामान्य जनमानस तक पहुँचाने एवं इनकी उपयोगिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से 26 पवन पम्प राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थापित कर दिए गए हैं जो सुचारु रूप से कार्य कर रहे है। पवन पम्प के साथ-साथ गाँवों में ईंधन समस्या का विकल्प सौर चूल्हे एवं गोबर गैस संयंत्र का निर्माण करके सुझाया है। भारत सरकार के प्रकृतिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने इस महाविद्यालय को देश का क्षेत्रीय केन्द्र घोषित किया है जो प्रदेश सहित समीपवर्ती गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्यों के लिए भी जैव गैस संयंत्र निर्माण को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है।

सौर चुल्हों के निर्माण के साथ-साथ महाविद्यालय ने सौर ऊर्जा से वाष्पिकृत जल निर्माण यंत्र, पानी गरम करने के सौर चुल्हे भी विकसित किये हैं।

———

तकनीकी शिक्षा

इंजिनियरिंग कालेज

इंजिनियरिंग डिग्रीधारियों की मांग को पूरा करने के लिए राज्य में पाँच इंजिनियरिंग कालेज क्रमशः जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, पिलानी में चल रहे हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 985 छात्र प्रति वर्ष हैं। सत्र 1984–85 से इंजिनियरिंग कालेज कोटा में भर्ती क्षमता 90 से बढ़ाकर 180 कर दी गई है।

पोलिटेक्निक संस्थान

इंजिनियरिंग डिप्लोमाधारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अगस्त 83 में भरतपुर पोलीटेक्निक को पुनः जीवित किया गया तथा सत्र 1984–85 में 60 नये छात्रों की भर्ती भरतपुर में ही की गई।

विधान सभा के गत सत्र में राज्य सरकार के दिए हुये आश्वासन के अनुसार भीलवाड़ा में पोलिटेक्निक की स्थापना कर दी गई है तथा सत्र 1984–85 में भीलवाड़ा में 40 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

अब राज्य में विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्युट, उदयपुर तथा बाबा मुंगिया संस्थान, पिलानी एवं चांद शिल्प शाला जयपुर की मिला कर कुल 13 पोलिटेक्निक हैं जिनके अन्तर्गत 1235 छात्रों को भर्ती करने की क्षमता है। देश की नवीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार के सहयोग से जोधपुर पोलिटेक्निक में पोस्ट डिप्लोमा कम्प्युटर प्रोग्राम का कोर्स चालू किया गया है।

महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा की सुविधाएँ

महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए जयपुर में एक राजकीय महिला पोलिटेक्निक खोला गया है जिसमें महिलाओं की अभिरुचि के अनुसार कामर्शियल आर्टस, टेक्सटाईल डिजाइन तथा ड्रेस मैकिंग और केस्टयुम डिजाइन व्यवसायों में कुल 60 छात्राओं को प्रति वर्ष तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य की अन्य पोलिटेक्निक संस्थानों में महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। इसके उपरान्त जयपुर में एक निजी संस्थान

चांद शिल शाला में भी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और एक विषय के लिए यह प्रावैधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर से संबंद्ध है ।

खाद्य कला संस्थान, जयपुर

राज्य में होटल उद्योग में विभिन्न श्रेणी एवं योग्यताओं के कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए जयपुर में एक खाद्य कला संस्थान चलाया जा रहा है, जिसे राज्य सरकार शत प्रतिशत खर्चा अनुदान के रूप में देती है ।

फूड क्राफ्ट संस्थान में सत्र 1983–84 से अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 प्रशिक्षणार्थी भर्ती किये गये हैं । इस विशेष प्रशिक्षण का खर्चा अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वहन किया जा रहा है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

वर्ष 1984–85 में नये छः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः जैसलमेर जालौर, झालावाड़, करौली, टोंक और धौलपुर में चालू किये गये हैं । अब राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और सारे राज्य में कुल 30 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विद्यमान हैं । जिनमें प्रति वर्ष 4552 छात्रों को प्रशिक्षण देने की सुविधा उपलब्ध है ।

महिलाओं को दस्तकार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए जयपुर में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलग से स्थापित किया गया है । राज्य की अन्य सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं ।

अनुसूचित जाति कम्पोनेंट प्लान

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत के अनुसार 815 प्रशिक्षण स्थान तो उपलब्ध हैं ही, इसके उपरान्त हर यूनिट में (व्यवसाय कक्षा में) 2–2 अतिरिक्त छात्र भर्ती किये जाते हैं । इन अतिरिक्त छात्रों के 358 स्थान हैं । इस प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कुल मिला कर 1173 (815+358) स्थान उपलब्ध हैं ।

जनजाति क्षेत्र उप-योजना

जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत आदिवासी छात्रों को दस्तकार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आबूरोड़ में चलाए जा रहे है, जहां पर आदिवासी छात्रों के लिए 60 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उत्पादन क्षेत्र (ट्राईजम योजना)

ग्रामीण युवकों को दस्तकार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में चार प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर में चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नवम्बर 83 में शाहपुरा में एक नया उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों में लघु अवधि के व्यवसायिक प्रशिक्षण चलाए जाते हैं। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत 1546 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

सामुदायिक पोलिटेक्निक की स्थापना

ग्रामीण समाज की सेवा और उत्थान के लिए जोधपुर और उदयपुर पोलिटेक्निक से सामुदायिक पोलिटेक्निक प्रकोष्ठ (Community Polytechnic) स्थापित करके गांवों के चौमुखी विकास के लिए तरह-तरह की योजनाएँ जैसे सड़कें बनाना, गोबर गैस प्लांट, दस्तकारों को नई तकनीकी का ज्ञान आदि क्रियान्वित की गई।

वर्ष 1984–85 में अजमेर पोलिटेक्निक संस्थान में भारत सरकार के सहयोग से अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को इंजिनियरिंग एवं गैर इंजिनियरिंग व्यवसायों के तकनीकी शिक्षा सुलभ कराने के लिए एक नया सामुदायिक पोलिटेक्निक प्रकोष्ठ, पोलिटेक्निक अजमेर में स्थापित किया गया। इस प्रकोष्ठ के अधीन अजमेर शहर में चार उप केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

भाषा विभाग

राज भाषा हिन्दी के राजकाज में प्रयोग, विकास और संवर्धन हेतु भाषा विभाग योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रहा है।

हिन्दीकरण

आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने पेंशन सम्बन्धी समस्त कार्य अनिवार्यत: हिन्दी मे किये जाने का निर्णय लेकर इस आशय के आदेश जारी किये ।

इस वर्ष विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जारी होंने वाले आदेशों परिपत्रों तथा राजपत्र में मुद्रणीय सामग्री एवं हिन्दी पत्रों में दिये जाने वाले विज्ञापनों में हिन्दी का ही प्रयोग हो इसकी अनुपालना हेतु नियमित रूप से कार्यवाही कर जिस विभाग/निगम/कार्यालय से कोई आदेश/विज्ञापन अंग्रेजी में जारी पाया गया उसे तथा उसके नियंत्रक अधिकारी को तुरन्त पत्र लिखकर के आदेशों की अनुपालना कड़ाई से करने हेतु अनुरोध किया गया ।

गोपनीय प्रतिवेदनों (वार्षिक मूल्यांकन) में हिन्दी का ही प्रयोग हो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किये । हिन्दी पदनामों की एकरूपता के लिये मुख्य सचिव जी ने निर्देश जारी किये कि विधिक रूप से मान्य हिन्दी पदनामों का प्रयोग किया जाये । राजस्थान सरकार के समस्त विभाग भारत सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों से हिन्दी में ही पत्राचार करें ऐसे निर्देश भी राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये ।

भाषा मंत्रीजी ने समस्त अर्द्ध सरकारी संस्थानों निगमों के अध्यक्षों को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखकर यह अनुरोध किया कि उनके यहां के समस्त कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की व्यवस्था की जाये और इसके सुनिश्चियन के लिये आवश्यक कदम उठये जायें । इसके क्रम में अनेक संस्थानों में राजभाषा-क्रियान्वयन समितियां गठित किये जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । राज्य सरकार ने नवगठित बिक्रीकर अधिकरण को निर्देश दिये हैं कि सारी कार्यवाही हिन्दी में की जाये और निर्णय हिन्दी में दिये जाये ।

हरिश्चन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान की सम्पूर्ण प्रशिक्षण सामग्री का क्रमिक रूप से हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है ताकि प्रशासनिक एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी हो सके तथा प्रत्येक प्रशिक्षण में उनसे सम्बन्धित कार्य हिन्दी में करने का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जा सके । प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है ।

इस वर्ष केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के तत्त्वावधान में केन्द्रीय राजभाषा सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार की अध्यक्षता में गठित

शब्दावली समन्वय समिति द्वारा हिन्दी की प्रशासनिक शब्दावली की केन्द्र तथा हिन्दी भाषी राज्यों में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु बैठकें आयोजित की गई जिनमें इस राज्य ने सक्रिय सहयोग देकर शब्दावली को अन्तिम रूप दिया।

अनुवाद

असांविधिक अंग्रेजी सामग्री का हिन्दी अनुवाद इस विभाग का प्रमुख कार्य है। आलोच्य वर्ष में 650 अंग्रेजी पृष्ठों की सामग्री का अनुवाद किया गया जिनमें से प्रमुख है हरिश्चन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का अनुवाद, निदेशक, पेंशन विभाग से प्राप्त प्रपत्र एवं मेन्यूअल तथा पुलिस आचरण संहिता का अनुवाद आदि।

प्रकाशन

आलोच्य वर्ष में दैनिक काम आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक प्रारूपों की पुस्तिका मुद्रणाधीन है। यह राज्य कर्मचारियों को हिन्दी में राजकाज करने में अभ्यास कराने में भी सहायक होगी तथा विभिन्न प्रशिक्षणों में काम आयेगी। विभागीय पत्रिका "भाषा परिचय" का नया अंक भी मुद्रणाधीन है।

समारोह एवं प्रदर्शनी

आलोच्य वर्ष में भाषा विभाग एवं सिन्ध राजस्थान राष्ट्र भाषा प्रचार समिति जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन द्विदिवसीय कार्यक्रम के रूप में किया गया।

हिन्दी दिवस की पूर्व संध्या पर वरिष्ठ साहित्यकार एवं कादम्बिनी-सम्पादक श्री राजेन्द्र अवस्थी की अध्यक्षता में काव्य गोष्ठी हुई जिसमें श्री बशीर अहमद "मयूख" एवं श्री नन्द चतुर्वेदी आदि मूर्धन्य कवियों ने भाग लिया।

दिनांक 14-9-84 को मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर "राष्ट्रीय एकता और हिंदी" विषय उच्च स्तरीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें देश के शीर्षस्थ साहित्यकारों, राज्य के न्यायमूर्तियों, वरिष्ठ पत्रकारों, अधिकारियों और हिन्दी सेवियों ने भावात्मक एकता में हिन्दी की भूमिका पर विचार रखे। गोष्ठी की अध्यक्षता तत्कालीन राजस्व मंत्री ने की तथा समारोह के मुख्य अतिथि तत्कालीन वित्त मंत्री थे।

इस अवसर पर एक राजभाषा प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसका उद्घाटन तत्कालीन उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री ने किया। इसमें हिन्दी के चहुंमुखी विकास को दर्शाया गया था। प्रदर्शनी में भाषा विभाग, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने भाग लिया।

शोध संदर्भ पुस्तकालय

भाषा विभाग द्वारा एक शोध संदर्भ पुस्तकालय चलाया जा रहा है। इसमें 8500 पुस्तकें हैं। आलोच्य वर्ष में 100 नई पुस्तकें खरीदी गईं।

हिन्दी शीघ्रलिपि प्रशिक्षण

राज्य में सेवारत शीघ्रलिपिकों, टंककों तथा अन्य लिपिवर्गीय कर्मचारियों को हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण देना विभाग का प्रमुख कार्य है। आलोच्य वर्ष में 70 कर्मचारियों हेतु हिन्दी शीघ्रलिपि प्रशिक्षण के दो सत्र संचालित किये गये। अब तक हिन्दी शीघ्रलिपि में लगभग 2300 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये हैं।

हिन्दी टंकण यन्त्रों का वितरण

विभाग द्वारा अंग्रेजी टंकण यन्त्रों के बदले में हिन्दी टंकण यन्त्र देने की व्यवस्था की जाती है। राजकीय विभागों द्वारा अंग्रेजी टंकण यन्त्रों की नई खरीद पर पूर्ण नियन्त्रण इस विभाग द्वारा रखा जाता है। आलोच्य वर्ष में विभिन्न विभागों को 60 टंकण यन्त्र दिये गये।

अनुदान

सिन्ध राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जयपुर को हिन्दी-दिवस समारोह के लिए 2000/- रुपये व तथा गिरिधर शर्मा नवरत्न जन्म शताब्दी समारोह के लिए राजस्थान हिन्दी साहित्य सम्मेलन, जयपुर को 2000/- रुपये की राशि का अनुदान दिया जा चुका है एवं अहिन्दी भाषियों को हिन्दी प्रशिक्षण तथा शीघ्रलिपि एवं टंकण प्रशिक्षण के लिए कक्षाएँ संचालित करने वाली संस्थाओं को भी अनुदान दिया जा रहा है।

———

राष्ट्रीय केडिट कोर

विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं में अनुशासन, साहस, एकता, चरित्र बल तथा समाज सेवा की भावना के विकास के लिए राजस्थान में एन. सी. सी. निदेशालय सन् 1963 में स्थापित किया गया था। उस समय 14 एन.सी.सी. इकाइयाँ थीं। उत्तरोतर विकास के फलस्वरूप अब तक चार ग्रुप मुख्यालय व 35 एन.सी.सी. इकाइयां कार्यरत हैं। इनमें चार हवाई प्रशिक्षण, तथा दो जल प्रशिक्षण इकाइयाँ हैं। शेष थल प्रशिक्षण इकाइयाँ हैं। ~~इनमें छात्राओं की चार प्रशिक्षण इकाइयाँ हैं~~। इनमें छात्राओं की चार प्रशिक्षण इकाइयां स्वतंत्र रूप से स्थापित हैं। राजस्थान में सीनियर डिवीजन में 26418 तथा जूनियर डिवीजन में 27300 छात्र/छात्रायें हैं।

वार्षिक प्रशिक्षण शिविर

इस वर्ष 26 वार्षिक शिविर लगाये गये जिनमें सीनियर डिविजन तथा जूनियर डिविजन के 15556 केडिट्स ने भाग लिया।

उपरोक्त वार्षिक शिविरों के अतिरिक्त महानिदेशक एन. सी. सी., नई दिल्ली द्वारा विभिन्न स्थानों पर 6 शिविर आयोजित किये गये जिसमें राजस्थान से केडिट्स ने भाग लिया। इस प्रकार के शिविर साधारणतया ग्रीष्म अवकाश में लगाये जाते हैं।

पैरा ट्रेनिंग

इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत 12 स्थान आवंटित किये गये जिनमें से 11 केडिट सफल हुये।

नियमित सेना के लिए चयनित

निम्नलिखित एन. सी. सी. केडिट सेना के लिए चयनित किए गये :—

1—जल सेवा विंग–2

2—वायु सेना विंग–4

सामाजिक सेवा

वर्ष 1983–84 में एन.सी.सी. छात्रों ने निम्नलिखित सामाजिक कार्य किए :—

1. वृक्षारोपण

इस वर्ष एन० सी० सी० में 3500 छात्रों ने 55882 वृक्ष लगाये जिनमें 51832 वृक्ष अच्छी हालत में हैं।

2. रक्त दान

इस वर्ष 253 एन० सी० सी० केडिट्स ने रक्तदान किया।

3. सफाई

368 एन० सी० सी० केडिटस ने स्कूल फर्नीचर, पानी की टंकी, पानी के पाईप, हॉल एवं परेड के मैदान को साफ किया।

4. एन० सी० सी० के 150 केडिट्स ने गाँव ढाकर केड़ी में दिनांक 1 अक्टूबर, 83 से 31 अक्टूबर, 83 तक ग्राम के व्यक्तियों को सफाई, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल, वृद्धों की शिक्षा व परिवार कल्याण के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाया।

5. एन० सी० सी० के 717 केडिट्स ने वर्ष 1984 में दहेज प्रथा के खिलाफ राजस्थान के बहुत से स्थानों पर अभियान चलाया तथा शपथ ग्रहण कराई।

6. एन० सी० सी० के 225 केडिट्स ने यातायात नियन्त्रण का कार्य किया।

साहसिक कार्य

इस वर्ष एन० सी० सी० के द्वारा निम्नलिखित साहसिक कार्य आयोजित किये जिनमें छात्रों ने भाग लिया—

1.	घुड़ सवारी	2
2.	ट्रीकींग अभियान	9
3.	सेलिंग अभियान	2
4.	साईकिल	3
5.	पर्वतारोह[illegible] अभियान	

उपरोक्त अभियोजन में 388 एन० सी० सी० केडिट्स ने भाग लिया।

Sub-National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 2716
Date 29.10.85

कोर्स

निम्न छात्रों ने पर्वतारोहण कोर्स में भाग लिया—

(क)	बेसिक कोर्स	—9
(ख)	एडवन्चर कोर्स	—3
(ग)	एस के ग्राई कोर्स	—2
(घ)	सिविल डिफेन्स इन्सट्रक्टर कोर्स	—1

एन.सी.सी. दिवस

गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी माह नवम्बर के अन्तिम रविवार को राष्ट्रीय केडिट कोर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्र के विशिष्ट व्यक्तियों एवं उच्च अधिकारियों के सामने एन.सी.सी. कार्य-कलापों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने झण्डारोहण किया तथा केडिट्स के मार्च पास्ट की सलामी ली।

वित्तीय आँकड़े

राष्ट्रीय केडिट कोर के लिये भारतीय सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त राज्य सरकार से वर्ष 1984–85 के लिये 160.34 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत है, तथा वर्ष 1985–86 के लिये 185.03 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

राजस्थान साहित्य अकादमी

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर की स्थापना 28 जनवरी, 1958 को राज्य सरकार ने राज्य के साहित्यिक विकास तथा साहित्यकारों के संरक्षण-सहयोग के निमित की तथा नवम्बर, 1962 में इसे स्वायत्तता प्रदान की गई। तब से अकादमी अपने विधान में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सतत् प्रयत्नशील है।

राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पिछले वर्ष नया संविधान लागू किये जाने के पश्चात् राजस्थान तथा राजस्थान के बाहर के अधिकाधिक साहित्यकारों को अकादमी से जोड़ने का कार्य किया है इसके साथ ही रजत

जयन्ती वर्ष पर अनेक समारोह तथा क्षेत्रीय उपनिषदों का आयोजन कर प्रान्त में साहित्यिक चेतना जागृत की है।

प्रकाशन : साहित्य अकादमी की एक मुख्य प्रवृत्ति राजस्थान के कृतिकारों की रचनाओं का प्रकाशन किया जाना है। सत्र 1984–85 में अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है—

1.	क्रान्तिकारी बारहठ केसरीसिंह व्यक्तित्व और कृतित्व [प्रथम खण्ड]	1. सं. डा. देवीलाल पालीवाल 2. सं. डा. ब्रजमोहन जावलिया 3. सं. श्री फतहसिंह मानव
2.	राजस्थान के हास्य व्यंग्यकार	सं. डा. मदन केवलिया
3.	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुनर्मूल्यांकन	सं. डा. प्रकाश आतुर
4.	साहित्य के सामयिक प्रश्न	सं. डा. प्रकाश आतुर

प्रकाशन सहयोग

अकादमी ने राज्य के साहित्यकारों को अधिकाधिक सहयोग देने तथा उनके साहित्य प्रकाशन के निमित्त पाण्डुलिपियाँ आमन्त्रित कर पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिये 38000/- रु. की राशि स्वीकृत की है।

मधुमती

अकादमी ने प्रान्त के सृजनधर्मियों को अखिल भारतीय स्तर पर प्रोजेक्ट करने का कार्य मधुमती के माध्यम से किया है। सत्र 1984–85 में मधुमती के 12 अंक प्रकाशित हुये हैं इसमें दो विशेषांक [1] संगोष्ठी विशेषांक तथा [2] आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुनर्मूल्यांकन विशेषांक प्रकाशित किए हैं, जिसे साहित्य जगत में बहुत सराहा गया है। इस सत्र में कृतिकार योजना के अन्तर्गत 8 लेखकों को प्रोजेक्ट किया गया है।

सहयोग

साहित्यकारों को उनके प्रकाशित ग्रन्थों पर सहयोग योजनान्तर्गत 8 ग्रन्थों को 9500/— रु. का आर्थिक सहयोग दिया गया है। राज्य की 9 संस्थाओं को प्रसारात्मक साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए 10500/– रु. स्वीकृत किये हैं। राजस्थान से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिकाओं को 6000/– रु. का आर्थिक सहयोग स्वीकृत किया गया है। झाबरमल शर्मा फेलोशिप राजस्थान के नाट्य लेखक व रंगकर्मी श्री मंगल सक्सेना को 500/– रु. मासिक दी जा रही है।

साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार कल्याण कोष से राजस्थान विभिन्न अंचलों में रहने वाले अभावग्रस्त तथा रुग्ण साहित्यकारों को उन इलाज के लिए अब तक 32,300/– रु. अनुदान दिया जा चुका है।

पुरस्कार

इस वर्ष 12 पुरस्कारों की घोषणाएं करदी गई हैं जिसमें ग्यार हजार रुपये का मीरां पुरस्कार प्रो. विजेन्द्र को उनकी कृति "लाल टहनी" प मिला है। पांच-पांच हजार रुपये के 4 पुरस्कार [1] सुधीन्द्र पुरस्कार [2] कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, [3] देवराज उपाध्याय पुरस्कार, [4] देवीला साभर पुरस्कार क्रमशः डा. जयसिंह नीरज जयपुर, डा. शिवकुमार शर्मा उदयपु प्रो. सूरजनदास स्वामी अजमेर तथा रिज़्वान जहीर उदयपुर को मिले हैं सुमनेश जोशी पुरस्कार श्री सत्यनारायण बीजावत, अजमेर को मिला है पत्र-कारिता के लिये जगदीशप्रसाद दीपक पुरस्कार सम्बोधन पत्रिका कांकरोल को मिला है।

अकादमी द्वारा महाविद्यालय तथा विद्यालय स्तर पर भी छात्रों निबन्ध आमन्त्रित कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। इस पुरस्कार का ना चन्द्रदेव शर्मा पुरस्कार रखा गया है। इस वर्ष महाविद्यालय स्तर पर प्रथ श्री हेमेन्द्र चण्डालिका उदयपुर तथा द्वितीय श्री गोपाल शर्मा उदयपुर रहे विद्यालय स्तर पर "परदेशी पुरस्कार" का प्रथम पुरस्कार सुश्री जाविद अजु डूंगरपुर को तथा द्वितीय पुरस्कार कु. अनिता सोमाणी अजमेर को मिला है।

पुस्तकालय

साहित्य अकादमी का अपना एक पुस्तकालय तथा शोध केन्द्र है जिससे कई शोधार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। अकादमी पुस्तकालय वाचनालय हाल पूर्ण होने को है। पुस्तकालय हाल के लिये राज्य सरकार से प्रदत्त अनुदान के अलावा नगर विकास प्रन्यास उदयपुर तथा नगर परिषद उदयपुर से भी अनुदान प्राप्त हुआ है।

टेप लाईब्रेरी

साहित्य अकादमी की एक टेप लाईब्रेरी योजना भी है जिसके अन्तर्गत अब तक राजस्थान के विभिन्न अंचलों के 11 [ग्यारह] रचनाकारों की वाणी टेप की जा चुकी है।

पाठ्यक्रम-विचार विमर्श केन्द्र

साहित्य अकादमी द्वारा राज्य के विभिन्न अंचलों में साहित्यिक वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से 20 पाठक मंच तथा 6 अध्ययन विचार विमर्श केन्द्र प्रारम्भ किए हैं।

साहित्यिक समारोह

साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान के विभिन्न अंचलों में समारोह तथा उपनिषदों का आयोजन किया है। इसमें राजस्थान लेखिका सम्मेलन कोटा, राजस्थानी युवा लेखक शिविर लक्ष्मणगढ़, आंचलिक समारोह रतनगढ़, आंचलिक समारोह झालावड़, आंचलिक समारोह डूंगरपुर, आंचलिक समारोह बाड़मेर प्रमुख हैं। माह फरवरी में एक आंचलिक समारोह श्रीकरणपुर में तथा राजस्थानी लेखक सम्मेलन का आयोजन बीकानेर में एवं साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है। अकादमी द्वारा इन आंचलिक समारोहों के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया।

साहित्य अकादमी द्वारा सृजन साक्षात्कार योजना के अन्तर्गत जयपुर, किशनगढ़, जालौर, श्री डूंगरगढ़, श्रीगंगानगर और सीकर में सृजन साक्षात्कार का आयोजन किया गया है।

सम्मान

साहित्य की उल्लेखनीय सेवाओं के फलस्वरूप अकादमी ने इस वर्ष साहित्यकारों को सम्मानित करने का निर्णय किया है।

राजस्थान संस्कृत अकादमी

जोधपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 11 फरवरी, 84 को माघ जयन्ती समारोह मनाया गया, जिसमें महाकवि माघ के कृतित्व पर पत्र वाचन किये गये॥

महाविद्यालय संस्कृत छात्रों की एक सामान्य प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

अप्रेल में राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में अकादमी का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अकादमी द्वारा संचालित वेद विद्यालयों के छात्रों की सहिता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर 3000 रुपये का माघ पुरस्कार जोधपुर निवासी श्री हरिराय गोस्वामी को प्रदान किया गया।

इसी अवसर पर अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन का आयोजन भी रखा गया जिसमें राजस्थान के व देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

सितम्बर, 84 में चुरू में एक संस्कृत समारोह आयोजित किया गया जिसमें संस्कृत के 3 मूर्धन्य विद्वानों को सम्मानित किया गया।

चूरू नगर में ही महाविद्यालयीय संस्कृत वादविवाद तथा श्लोक पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस वर्ष माघ पुरस्कार की राशि 3000/- रुपये से बढ़ाकर 5000/- रुपये कर दी गई है। इस वर्ष का माघ पुरस्कार उदयपुर निवासी श्री गिरधारीलाल व्यास को प्रदान किया गया है।

अकादमी ने वेद विद्या के संवर्धनार्थ वैदिक विद्वान् को दिया जाने वाला मधुसूदन ओझा पुरस्कार प्रारम्भ किया है जो इस वर्ष जयपुर के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान पं. शिवप्रताप शर्मा को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की राशि 1001/- रुपये है। अकादमी की संस्कृत पत्रिका स्वरमंगला में प्रकाशित सर्वोत्तम रचना पर अम्बिकादत्त व्यास पुरस्कार भी दिया जाता है। जिसकी राशि 501/- रुपये है। इस वर्ष पण्डित खड्गनाथ मिश्र एवं डॉ शिवसागर त्रिपाठी दोनों में से प्रत्येक को 501/- रु. का यह पुरस्कार दिया गया।

अकादमी ने संस्कृत प्रचार-प्रसार के लिये दो गोष्ठियों का आयोजन किया जिनमें संस्कृत काव्य संध्या तथा ज्योतिष में राजयोग पर विचार चर्चा रखी गई। फरवरी माह में अकादमी का वार्षिकोत्सव तथा डा. राजेन्द्रप्रसाद जन्म शताब्दी समारोह भारत के उपराष्ट्रपति के सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर स्वरमंगला के राजेन्द्रप्रसाद शती विशेषांक का विमोचन भी हुआ। इस वर्ष से अकादमी के अन्तर्गत वीरेश्वर पुस्तकालय शोधार्थियों के उपयोगार्थ प्रतिदिन 8 घण्टे के लिये खोला जा रहा है।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

सन् 1968 में शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के हिन्दी माध्यम में लिखवाने की योजना के अन्तर्गत विशेषत: राजस्थान प्रान्त में स्थापित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अब तक मानविकी, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की 320 पुस्तकों का प्रकाशन किया है।

इस अकादमी द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों एवं विद्यार्थियों को अब तक रुपये 52,81,525.30 ग्रास मूल्य की पुस्तकें विक्रय द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। वर्ष 1984-85 में लगभग 4,61,000 रुपयों की पुस्तकों का विक्रय हुआ है।

अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के प्रचार-प्रसार एवं विक्रय संवर्धन हेतु उदयपुर, जोधपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालयों एवं जयपुर के महाविद्यालयों तथा अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि के महाविद्यालयों में पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गई।

अकादमी द्वारा प्रकाशित पस्तकों में से 93 पुस्तकें विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में समाविष्ट हैं तथा 24 पुस्तकें विभिन्न राज्यों द्वारा पुरस्कृत की गई हैं।

वर्तमान में विश्वविद्यालय स्तर के 119 ग्रन्थ लेखनाधीन हैं। 14 पुस्तकें समीक्षाधीन हैं। अब तक अकादमी ने 45 ग्रन्थों के पुनर्मुद्रण-द्वितीय एवं तृतीय संस्करण भी प्रकाशित किये हैं।

राजस्थान उर्दू अकादमी

गरीब साहित्यकारों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता :

आलोच्य वर्ष में अकादमी द्वारा पांच बीमार साहित्यकारों को चिकित्सा हेतु रुपये 1500/- की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 15 शायरों तथा पांच विधवाओं को (जो प्रसिद्ध शायरों की पत्नियां हैं।) क्रमश: 1200/- (रुपये सौ प्रतिमाह की दर से) तथा रुपये 600/-

विधवाओं को (रुपये पचास प्रतिमाह की दर से) आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये गये।

कौमी एकता

आलोच्य वर्ष में कौमी एकता सप्ताह के अन्तर्गत दिनांक 24 नवम्बर 1984 को एक अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया गया।

अकादमी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका नखलिस्तान का प्रकाशन अप्रेल 1981 से सुचारू रूप से किया जा रहा है।

विविध

अकादमी के पुस्तकालय में 1975 पुस्तकें हैं और उसके वाचनालय में उर्दू, हिन्दी तथा अंग्रेजी के कई पत्र आते हैं।

जयपुर में किताबत स्कूल की स्थापना हुए दो साल पूरे हो गये हैं। यह स्कूल केन्द्रीय सरकार के शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालय के उर्दू मोन्नति ब्यूरो द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त कर संचालित की जा रही है। किताबों का पहला बैच इसी माह तैयार होकर अपना स्वतन्त्र व्यवसाय प्रारम्भ कर देगा।

निर्धन छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण

अकादमी द्वारा प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के निर्धन छात्रों को उर्दू की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जाती हैं।

हिन्दु मुस्लिम कौमी एकता संघ जयपुर द्वारा कौमी एकता पर एक संगोष्ठी का आयोजन जोलाई 1984 में किया गया था। इसके लिये अकादमी द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग द्वारा अन्य साहित्यक गतिविधियां भी अकादमी की आर्थिक सहायता द्वारा दिसम्बर 1984 में संचालित की गई। 15 निर्धन छात्रों को 300 रुपये सालाना के हिसाब से दी गई।

राजस्थान सिन्धी अकादमी

राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिन्धी अकादमी का गठन वर्ष 1979

में किया। इस अकादमी द्वारा वर्ष 1984 में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

अकादमी ने अपने वार्षिकोत्सव के अवसर पर सिन्धी समाज के विभिन्न क्षेत्रों के निष्ठावान व्यक्तियों का अभिनन्दन किया। समाज सेवा क्षेत्र, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा पत्रकारिता आदि क्षेत्रों के लब्ध प्रतिष्ठित, व्यक्तियों की शाल ओढ़ाकर, प्रशंसा पत्र व ट्राफी देकर सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया।

सिन्धी समाज के युवा कार्यकर्ता श्री भगवानदेव आचार्य, सांसद की उत्कृष्ट सेवाओं के कारण उनको "सिन्धी रतन" की उपाधि से विभूषित किया गया।

अकादमी द्वारा एक विशाल दहेज विरोधी सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें दहेज विरोधी विषयों पर पत्र वाचन किये गये एवं 25 वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर दहेज विरोधी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा अकादमी द्वारा आयोजित दहेज विरोधी नाटक लेखन प्रतियोगिता में पुरस्कृत नाटकों के संकलन का भी विमोचन किया गया।

इस वर्ष अकादमी ने नई पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने हेतु नई योजना आरम्भ की है। राजस्थान के सिन्धी रचनाकारों को अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के लिये वित्तीय सहयोग के रूप में अकादमी द्वारा 1000/– रु. दिये जाते हैं। अब तक लगभग 20 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है।

अकादमी ने सिन्धी के गद्य-पद्य की प्रकाशित पुस्तकों पर नकद पुरस्कार देने की योजना चला रखी है। इस वर्ष अजमेर के श्री ईश्वरचन्द्र व जयपुर के श्री आशा दुर्गापुरी को दो-दो हजार रुपये के नकद पुरस्कार दिये गये हैं।

हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी तीन जरूरतमन्द साहित्यकारों को 600 रु. प्रतिवर्ष की दर से आर्थिक सहायता (1800 रु.) प्रदान की गई।

सिन्धी के महाकवि श्री किशनचन्द बेवस के जन्म शताब्दी के अवसर पर अकादमी द्वारा श्री पदमराज शर्मा की लिखी हुई पुस्तक "कवि किशनचन्द्र बेवस" का हिन्दी में प्रकाशन किया गया है जिससे हिन्दी भाषा के लोगों को भी सिन्धी के महान साहित्यकारों से सम्बन्धित साहित्य का ज्ञान हो सके।

———

राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी

राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर की स्थापना 25 जनवरी 1983 को हुई। अकादमी की स्थापना के बाद से लेकर अब तक अकादमी राजस्थानी भाषा एव संस्कृति के प्रचार-प्रसार में निरन्तर प्रगति कर रही है।

अकादमी ने पूर्व पुरस्कार परम्परा को जारी रखते हुये इस वर्ष राजस्थानी की सर्वश्रेष्ठ कृति पर "महाकवि सूर्यमल्ल मिसरण" पुरस्कार योजनान्तर्गत 11000/- रुपये का पुरस्कार रखा है। इसी प्रकार इस सत्र से भाषा, साहित्य संस्कृति, पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ठ कार्य करने वाले साहित्यकारों की सेवाओं के सम्मानार्थ 5 हजार रुपये प्रदान करने की योजना है।

अकादमी अनुदान योजनान्तर्गत लेखकों के निजी व्यय से प्रकाशित ग्रन्थों पर आर्थिक सहायता देनी है। साहित्यकार सम्मान सहयोग योजनान्तर्गत रुग्ण साहित्यकारों की आर्थिक मदद की योजना चालू है।

अकादमी ने पूर्व की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के चार अंचलों में आंचलिक समारोह मनाने का निश्चय किया है जिनमें कोटा-अंचल का समारोह सम्पन्न हो चुका है तथा बांसवाड़ा, जोधपुर. लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में आंचलिक समारोह किये जा चुके हैं।

अकादमी ने इसी वर्ष मार्च के अन्त में राजस्थानी लोक संस्कृति समारोह मनाने का निश्चय किया है जिसमें प्रदेश के लोक कलाकारों को बुलाया जायेगा एव उन्हें सम्मानित किया जायेगा।

अकादमी अपने वार्षिक समारोह के अवसर पर राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय एकता के महत्व को ध्यान में रखकर देश की सभी अकादमियों के अध्यक्षों एवं सचिवों का सम्मेलन भी अगस्त-सितम्बर 1985 में जयपुर में आयोजित किया जायेगा।

मार्च 85 में जयपुर में राजस्थान की अकादमी का सम्मेलन आयोजित किया गया।

अकादमी की पत्रिका जागती-जोत का प्रकाशन भी मार्च 85 से विशिष्ट सामग्री के साथ मार्च के अन्तिम सप्ताह में प्रकाशित किया जा रहा है। जो अपने आप में एक उपलब्धि होगी।

राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति के शोध में सृजनात्मक साहित्यकारों, कलाकारों एवं विद्वानों की अपेक्षाओं और राजस्थानी भाषा परिवार की भावात्मक एकता को एकरूपता देने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं।

अकादमी ने राजस्थानी भाषा के प्रचार हेतु मुख्यालय स्तर पर राजस्थानी अध्ययन केन्द्र चालू कर रखा है जिसमें प्रदेश व देश के सैकड़ों विद्वानों ने लाभ लिया हैं।

अकादमी ने ग्रामीण अंचलों में भी प्रचार-प्रसार हेतु राजस्थानी केन्द्रों का शुभारम्भ किया है, जिसमें कोटा—श्री डूंगरगढ़ (चुरू), बांसवाड़ा, जोधपुर तथा लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में यह केन्द्र गत वर्ष से चालू हैं।

अकादमी ने अपनी योजनाओं में दो प्रकार के कार्यक्रम बनाये हैं।

जिसमें (1) अनिवार्य कार्यक्रम व (2) वैकल्पिक कार्यक्रम।

गुरु नानक भवन संस्थान, जयपुर

1969 में मनाये गये गुरु नानक देवजी के 500वें जन्म उत्सव के उपलक्ष में राजस्थान सरकार द्वारा इस छात्र सेवा संस्थान का निर्माण कराया गया था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास करना है।

इस वर्ष संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से 1100 छात्र-छात्रायें नये सदस्य बनकर लाभान्वित हुये तथा 10,000 से अधिक बिना सदस्य बने लाभान्वित हुये। प्रतिदिन 250 से अधिक छात्र-छात्रायें विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ग्रीष्मावकाश में यह संख्या 1000 प्रतिदिन तक पहुंच जाती हैं। पुस्तकालय एवं वाचनालय सेवा का 6,000 से अधिक छात्र-छात्राओं तथा अन्य व्यक्तियों ने लाभ उठाया।

इस संस्थान में स्पोर्टस काम्पलैक्स के अन्तर्गत प्रतिदिन औसत 100

छात्र/छात्रायें लाभान्वित हो रहे हैं। इस वर्ष भी संस्थान के चित्रकला क्लब के सदस्यों द्वारा दो बार चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ललित-कला एकेडेमी राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता 1985 में क्लब के 3 सदस्यों ने भाग लिया है।

राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष में उपलब्ध राशि से संस्थान प्रांगण में जवाहरलाल नेहरू विज्ञान दीर्घा हेतु एक कक्ष बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिनांक 14-11-83 को इस दीर्घा का शिलान्यास किया गया था। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है।

मई 1984 एवं जौलाई 1984 में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 1984 हेतु राजस्थान के छात्र/छात्राओं को तैयार करने के लिये प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। राजस्थान से 35 छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति में चयनित हुये। संस्थान में हर वर्ष की भाँति नवम्बर 1984 में बाल दिवस से लेकर प्रधानमन्त्री के जन्म दिन (14 नवम्बर से 19 नवम्बर तक) बाल समारोह एवं महिला दिवस का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

गत वर्ष संस्थान में एक एडवेन्चर क्लब की स्थापना की गई थी। इस क्लब के सदस्यों की संख्या 140 हो चुकी है। इस वर्ष सदस्यों द्वारा साईकिल यात्रा (जयपुर से वैष्णोदेवी, 1,000 कि. मी. साईकिल यात्रा), जयपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, जयपुर युवा दिवस के उपलक्ष में जयपुर में 40 कि. मी. मैराथन दौड़ तथा 80 कि. मी. जयपुर, चाकसू, जयपुर साईकिल दौड़ का आयोजन किया गया। संस्थान में प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित होती रहती हैं। जिनमें मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं—

खेलकूद, गृहसज्जा, पाककला, स्वयं सज्जा, फल संरक्षण, अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करना, सर्फ तथा साबुन बनाना, चित्रकला, नृत्य, अभिनय, संगीत. फोटोग्राफी, रेडियो एलेक्ट्रोनिक्स आदि आदि मुख्य हैं।

NIEPA DC
D02716
...stems Unit,
...e of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No...2716........
Date..29..10..85.....